भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत शुरू

राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बोले : व्यापार समझौता निकट है

यूएस व्यापार प्रतिनिधि से लगातार संपर्क में भारत

नई दिल्ली/वाशिंगटन, 25 दिसंबर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने संकेत दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक संतुलित और पारस्परिक लाभकारी ट्रेड डील होने वाली है. उन्होंने बताया कि व्यापार और शुल्क से जुड़े मुद्दों पर निरंतर संवाद जारी है.

इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूत नींव रखी. क्वात्रा ने एक्सिओम-4 मिशन और निसार मिशन का जिक्र करते हुए बताया कि अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और एआइ सहित कई क्षेत्रों में दोनों देश सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. राजदूत के अनुसार, ये पहल न सिर्फ व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देंगी, बल्कि द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेंगी. अमेरिकी संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण को दोनों देशों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया. क्वात्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले महीनों में व्यापार समझौते, अंतरिक्ष सहयोग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नई पहल की उम्मीद है.

> उनका उद्देश्य एक संतुलित और पारस्परिक लाभकारी ट्रेड डील को जल्द संभव बनाना है. क्वात्रा ने बताया कि फरवरी में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों की मजबूत नींव रखी. उस यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में ठोस समझौते पर सहमति बनी, जिनमें अंतरिक्ष सहयोग प्रमुख रहा. क्वात्रा ने एक्सिओम-4 मिशन का उल्लेख किया, जिसमें भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुँचे. यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था. इसके अलावा निसार मिशन को भी सफलतापूर्वक लांच और संचालन में लाया गया, जो भारत-यूएस अंतरिक्ष सहयोग की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण साबित हुआ. उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगभग सभी योजनाएं 10 महीने में पूरी हो गई हैं. राजदूत ने यह भी कहा कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में दोनों देश लगातार सक्रिय हैं. एआइ, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में साझेदारी को और सुदृढ़ किया जा रहा है.

संदीप बत्रा बने मुख्य मानव संसाधन अधिकारी

मुंबई. इस्पात, ऊर्जा और अन्य कारोबार में लगे प्रतिष्ठित जेएसडब्ल्यू समूह ने अपनी मानव संसाधन (एचआर) प्रबंधन टीम को और मजबूत बनाने के लिए संदीप बत्रा को प्रेसिडेंट एवं मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनाया है. कंपनी ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि बत्रा जेएसडब्ल्यू स्टील और कॉर्पोरेट विभाग में मानव संसाधन एवं प्रतिभा से जुड़ी कार्ययोजनाओं का नेतृत्व करेंगे. भारतीय सेना में कमीशंड ऑफिसर के रूप में काम कर चुके बत्रा को आईटी, उपभोक्ता, टेलीकॉम, रिटेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर और एविएशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा प्रबंधन, संगठनात्मक डिजाइन और उत्पादकता वृद्धि के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है. वह इससे पहले अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के मानव संसाधन प्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे.

लोकोमोटिव शेड साबरमती की अभिनव पहल

विकसित की इनोवेटिव वैक्यूम असिस्टेड ट्रैक क्लीनिंग डिवाइस

नई दिल्ली, 25 दिसंबर. भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत भारत को विनिर्माण, डिज़ाइन एवं नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अनेक सुधार किए जा रहे हैं.

इसी क्रम में विकसित भारत की संकल्पना एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद स्थित लोकोमोटिव शेड साबरमती ने नवाचार एवं स्वदेशी तकनीकी विकास के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. लोको शेड साबरमती की टीम द्वारा इन-हाउस रूप से एक वैक्यूम असिस्टेड ट्रैक क्लीनर (वीएटी क्लीनर) का सफलतापूर्वक डिज़ाइन एवं निर्माण किया गया है.

यह उपकरण पर्यावरण अनुकूल एवं लागत प्रभावी है,यह इको-फ्रेंडली और किफायती डिवाइस (एच एच पी लोकोमोटिव के रेडिएटर फैन का इस्तेमाल करके इन-हाउस बनाया गया है, जिसे एक डीज़ल वर्किंग ट्रॉली पर वर्टिकली लगाया गया है और यह लोकोमोटिव से ही पावर लेता है. रेडिएटर फैन चैंबर एक खास डिज़ाइन किए गए कचरा इकट्ठा करने वाले चैंबर से जुड़ा है, जिससे रेलवे ट्रैक और आस-पास के क्षेत्र से कचरा प्रभावी ढंग से हटाया जा सकता है. 1000 से 1800 आरपीएम की उच्च गति पर कार्य करने वाला यह उपकरण प्रभावी सक्शन प्रदान करता है. वैट क्लीनर के संचालन हेतु ड्राइवर डेस्क पर ऑन/ऑफ एवं वैरिएबल स्पीड कंट्रोल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे ड्राइवर अपनी सीट से ही सक्शन क्षमता को नियंत्रित कर सकता है.

भारत में अर्थव्यवस्था की बढ़ी रफ्तार

राउंडअप 2025

साल 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निवेश और बाजार के लिहाज से खास रहा. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने रिकॉर्ड 81 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया, जिसमें सर्विस सेक्टर निवेशकों की पहली पसंद बना. वहीं सरकार ने औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और कनेक्टिविटी को गति देने के लिए अनुपूरक बजट में बड़ा प्रावधान किया. शेयर बाजार में भी ज्यादातर बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने सकारात्मक रिटर्न दिया, जहां भारती और रिलायंस जैसे समूहों ने बढ़त बनाई. ये आंकड़े बताते हैं कि भारत निवेश, उद्योग और बाजार—तीनों मोर्चों पर मजबूती की ओर बढ़ रहा है.

वित्त वर्ष 2024-25 (एफवाई -2525) भारत के लिए विदेशी निवेश के लिहाज से भरोसे और मजबूती का साल साबित हुआ. इस दौरान भारत को कुल करीब 81.04 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 14त्न अधिक है. यह बढ़ोतरी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वैश्विक निवेशक भारत की आर्थिक स्थिरता, सुधारोन्मुख नीतियों और इज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कदमों पर भरोसा बनाए हुए हैं. एफवाई -25 में सबसे ज्यादा एफडीआई सर्विस सेक्टर में आया, जहां निवेश बढ़कर 9.35 अरब डॉलर पहुंच गया. डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और आउटसोर्सिंग ने भारत को निवेशकों की पहली पसंद बनाया. इसके साथ ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर-हार्डवेयर और ट्रेडिंग सेक्टर में भी मजबूत निवेश देखने को मिला. खास बात यह रही कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 18त्न की बढ़त दर्ज हुई, जो मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं के असर को दर्शाती है. कुल मिलाकरएफवाई-25 ने भारत को एक मजबूत, डिजिटल और भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में और स्थापित किया.

वंही, उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए अनुपूरक बजट 2025-26 में बड़ा दांव खेला है. औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि इस बार के अनुपूरक बजट में सबसे अधिक फोकस उद्योगों के विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर किया गया है. कुल 24,496.98 करोड़ रुपये के बजट में औद्योगिक विकास विभाग के लिए 4,874.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है. नंदी के मुताबिक, निवेश प्रोत्साहन नीतियों, एफडीआई आकर्षण और रोजगार सृजन योजनाओं के जरिए उत्तर प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है. बजट में जेवर एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के लिए भारी राशि आवंटित की गई है, जिससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से देश का ग्रोथ इंजन और वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है.

> वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल 81.04 अरब डॉलर का एफडीआई आकर्षित कर निवेशकों का भरोसा जताया. सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक 19त्न निवेश गया, जबकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ट्रेडिंग सेक्टर में भी विदेशी निवेश बढ़ा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 18त्न की वृद्धि ने 'मेक इन इंडिया' की प्रगति दर्शाई. इसी दौरान, उत्तर प्रदेश ने अनुपूरक बजट में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए कुल 4,874.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी बजट आवंटित किया गया. साल 2025 में देश के टॉप 10 बिजनेस ग्रुप्स में से 8 ने पॉजिटिव रिटर्न दिए. भारती ग्रुप की कंपनियों का कुल मार्केट कैप 30त्न बढ़ा, जबकि रिलायंस, आदित्य बिड़ला और बजाज ग्रुप ने भी शानदार प्रदर्शन किया. इसके विपरीत, टाटा और ढ्ढञ्ज ग्रुप को नुकसान झेलना पड़ा. यह संकेत देता है कि भारत में निवेश और आर्थिक विकास की दिशा मजबूत बनी हुई है.

एक साल में सेंसेक्स ने दिया नौ फीसदी रिटर्न

स्मॉलकैप के निवेशकों को नुकसान

नई दिल्ली, 25 दिसंबर. छोटी कंपनियों में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा. निफ्टी-50 साल के दौरान 10.56 **प्रतिशत चढ़कर** 26,142.10 **अंक पर बंद हुआ, वहीं बीएसई सेंसेक्स ने** 9.30 **प्रतिशत की बढ़त दर्ज की. मिडकैप सूचकांक मामूली वृद्धि के साथ बंद हुआ, लेकिन स्मॉलकैप सूचकांक में गिरावट रही.**

निवेशकों की भागीदारी बढ़ी और कुल बाजार पूंजीकरण 469 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा. साल 2025 शेयर बाजार के लिए मिश्रित परफॉर्मेंस लेकर आया. बड़े और मजबूत कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को

सेंसेक्स और निफ्टी से अच्छा रिटर्न मिला, जबकि छोटी कंपनियों में निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ा. निफ्टी-50 साल के दौरान 2,497.30 अंक यानी 10.56प्रतिशत बढ़कर 26, 142.10 अंक पर बंद हुआ. बीएसई सेंसेक्स ने भी 7,269.69 अंक यानी 9.30प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की.

> साल के दौरान एनएसई का कुल बाजार पूंजीकरण 469 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जो जीडीपी का 136प्रतिशत है. इक्विटी, डेट और बिजनेस ट्रस्ट के माध्यम से कुल 19.17 लाख करोड़ रुपये का फंड जुटाया गया. एनएसई में आईपीओ की संख्या में भी बढ़ोतरी रही. साल 2025 में 101 मेनबोर्ड आईपीओ के जरिए 1.71 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए, जबकि 112 छोटी और मझौली कंपनियों के आईपीओ से 5,589 करोड़ रुपये जुटे. घरेलू निवेशकों की संख्या 1.5 करोड़ बढ़कर 12.4 करोड़ हो गई. इक्विटी डेरिवेटिव कारोबार में एनएसई ने दुनिया में पहला स्थान बनाए रखा. साल 2025 में पहली बार एनएसई आईएक्स ने एक लाख करोड़ डॉलर का टर्नओवर पार किया और यह 1,106 अरब डॉलर तक पहुंचा. बाजार में घरेलू संपत्ति में पिछले पांच साल में लगभग 53 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे निवेशकों और इकॉनमी के लिए स्थिर और सकारात्मक संकेत मिले हैं.

भारत ने चीन, वियतनाम के एक-एक उत्पादों पर लगाया डंपिंग रोधी शुल्क

नई दिल्ली, 25 दिसंबर. भारत ने चीन और वियतनाम के एक-एक उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इस संबंध में बुधवार को अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं.

पहली अधिसूचना में कहा गया है कि वियतनाम से बड़ी मात्रा में सामान्य से कम मूल्य पर कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच का भारत को निर्यात किया जाता है. इस कारण भारतीय उद्योगों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का फैसला किया गया है. कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच का उपयोग प्लास्टिक उद्योग में किया जाता है. मूल रूप से वियतनाम में उत्पादित या वियतनाम से निर्यात किये गये . इस उत्पाद पर 75 डॉलर प्रति टन तक का शुल्क लगाया गया है. वियतनाम की जिन सात कंपनियों के नाम अधिसूचना में हैं उनके लिए 31.58 डॉलर से 39.25 डॉलर तक का डंपिंग प्रतिरोधी शुल्क लगाया गया है. अन्य सभी मामलों में 75 डॉलर प्रति टन का शुल्क देय होगा. वहीं, रेफ्रीजरेटरों और कारों के कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली और चीन से आयातित गैस 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोएथेन या आर-134ए पर भी डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की घोषणा की गई है. इस मामले में चीन की छह कंपनियों में बने उत्पादों पर 4,583 डॉलर प्रति टन तक का शुल्क लगाया गया है. चीन की अन्य कंपनियों में बने उत्पादों और चीन के बाहर बने लेकिन चीन से निर्यात किये गये उत्पादों पर 5,251 डॉलर प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगेगा.

आधी रात से प्रभावी हो जाएंगे बढ़े हुए रेल किराये

नयी दिल्ली 25 दिसंबर. रेल टिकट की संशोधित दरें गुरुवार आधी रात के बाद प्रभावी हो रही हैं जिनके अंतर्गत 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का सफर प्रति किलो मीटर एक से दो पैसे महंगा हो जाएगा।

रेलवे को किरायों में इस वृद्धि से सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है। भारती रेलव के यात्री विपणन प्रभाग के निदेशक प्रवीण कुमार की ओर से गुरुवार को इस संबंध में रेलवे के सभी जोन को परिपत्र भेज दिये गये हैं। नोटिस में कहा गया है कि वास्तविक संशोधित किराये वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार प्रभावी होंगे। नोटिस में कहा है कि यदि किसी यात्री ने किराया बढ़ोतरी का निर्णय घोषित होने की तिथि (21 दिसंबर) से पहले टिकट खरीद लिया है, तो उससे अतिरिक्त राशि नहीं वसूली जाएगी। रेलवे ने कहा है कि शुक्रवार से सभी स्टेशन पर टिकटों की नयी दरों के प्रभावी होने के संबंध में सूचना प्रसारित होगी।

2026 में भारत लौटेंगे विदेशी निवेशक

बैंकिंग-एनबीएफसी सेक्टर बनेगा फोकस

वित्त वर्ष 2027 में मुनाफा बढ़ने के संकेत

नई दिल्ली, 25 दिसंबर. भारतीय शेयर बाजार के लिए साल 2̀26 उम्मीदों से भरा नजर आ रहा है. एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बेहतर आय वृद्धि और अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते के चलते विदेशी संस्थागत निवेशक एक बार फिर भारत की ओर रुख कर सकते हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वैल्यूएशन निवेश के लिहाज से आकर्षक हैं और खासतौर पर बैंकिंग व एनबीएफसी सेक्टर में आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है. एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में भारतीय शेयर बाजार का आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है. निफ्टी का प्राइस-अर्निंग्स रेश्यो 20.5 गुना है, जो पिछले पांच वर्षों के औसत के बराबर और दस वर्षों के औसत से थोड़ा अधिक है. इसका संकेत है कि मौजूदा स्तरों पर निवेश के अवसर मौजूद हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 की सुस्त स्थिति के बाद वित्त वर्ष 2027 में निजी बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उनकी कमाई में मध्यम लेकिन स्थिर वृद्धि देखने को मिल सकती है.

समाचार विशेष

अजीत ने दिए एनसीपी गुटों के विलय के संकेत

क्या फिर एक होगा पवार परिवार..?

मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा एपी) के अध्यक्ष अजीत पवार ने मंगलवार को कहा कि राकांपा के दोनों गुटों का विलय होने की दिशा में चर्चा हो रही है. इस संबंध में वे खुद शुक्रवार को अधिकृत घोषणा करेंगे. वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे भी इस बात की पुष्टि की है.

अजीत पवार ने मुंबई में कहा कि दोनों पक्ष एक साथ मिलकर आगामी नगर निगम चुनाव लड़ेंगे. इस बाबत पार्टी के पदाधिकारी आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं. एक साथ मिलने के लिए कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ती है. इस चर्चा के बाद शुक्रवार को अधिकृत घोषणा वे खुद करेंगे. राकांपा (एसपी) के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा कि इस बाबत पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा की गई है. लगभग सभी पदाधिकारी राकांपा के दोनों गुटों को एक साथ रहने का समर्थन कर रहे थे. इसे देखते हुए अब पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं ने अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं का रुख भी भांपने का प्रयास किया है. कार्यकर्ताओं की भी इच्छा दोनों गुट के साथ रहने की है इसलिए वरिष्ठ स्तर पर इस बाबत निर्णय लिया जाएगा.

परिवार की कटुता दूर करने साथ आने का मन

> उल्लेखनीय है कि अजीत पवार ने राकांपा में बगावत कर पार्टी में ही अलग गुट बना लिया था. इसके बाद लोकसभा चुनाव में राकांपा (एसपी) को सफलता मिली थी, जबकि विधानसभा चुनाव में राकांपा एपी गुट को सफलता मिली थी, लेकिन पार्टी में हुए अलगाव का असर शरद पवार के परिवार पर पड़ रहा था. इसी परिवार की कटुता को दूर करने के लिए राकांपा के दोनों गुट एक साथ आने का मन बना रहे हैं. हालांकि अब शुक्रवार को पता चल सकेगा कि दोनों गुट एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं या फिर अपने-अपने चुनाव चिन्ह पर आगामी चुनाव लड़ते हैं. इस संबंध में अभी खुलासा नहीं हो सका है.

महाजंगलराज का जुमला कितना चलेगा

कोलकाता. ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा किसी बड़े नैरेटिव और नारे की तलाश में है. अभी तक उसे कोई एक सेंट्रल नैरेटिव और एक मुख्य नारा नहीं मिल पाया है. अब प्रधानमंत्री महाजंगलराज का नारा आजमा रहे हैं.

उन्होंने शनिवार, 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया तो रानाघाटा की सभा को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए महाजंगलराज का जुमला बोला. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महाजंगलराज को समाप्त करना है.

इस नारे का संदर्भ बिहार से लिया जाता है. यह अनायास नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के चुनाव नतीजों के बाद उसी दिन शाम में भाजपा मुख्यालय के स्वागत समारोह में कहा था कि बिहार से पश्चिम बंगाल का रास्ता बना है. उन्होंने कहा था कि गंगाजी बिहार से होकर बंगाल जाती हैं. यह बात उन्होंने रानाघाट की सभा को संबोधित करते हुए भी दोहराया. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का रास्ता बना है.

दिल्ली की सियासत में एक बार फिर चिट्ठी युद्ध

नई दिल्ली. दिल्ली की सियासत में एक बार फिर चिट्ठी युद्ध की आग भड़क उठी है. इस बार यह लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा तीखी और निजी हमलों से भरी नजर आ रही है. उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक 15 पन्नों का पत्र लिखा है, जिसमें न केवल उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं.

पत्र में उपराज्यपाल ने सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली में वर्तमान में इमरजेंसी जैसी स्थिति उत्पन्न होने के लिए केजरीवाल की सरकार की 11 साल की उपेक्षा और आपराधिक निष्क्रियता जिम्मेदार है. पत्र में आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया और चुनाव हारने के बाद संवाद के सभी रास्ते बंद कर दिए.

एक और निजी आरोप के तहत एलजी ने कहा कि चुनाव हारने के बाद केजरीवाल ने उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया. उन्होंने बताया कि दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए उन्होंने कॉल किया, लेकिन यह पता चला कि केजरीवाल ने उनका नंबर ब्लॉक कर रखा था.

पत्र के बड़े खुलासे

> वीके सक्सेना ने पत्र में लिखा कि जब वे मुख्यमंत्री थे और एलजी ने उनसे प्रदूषण की समस्या पर चर्चा की, तो केजरीवाल ने इसे केवल 15-20 दिनों का हंगामा बताते हुए हल्का फुल्का करार दिया. एलजी ने दावा किया कि केजरीवाल के इस रवैये के कारण मीडिया और एनजीओ वाले इस मुद्दे को भूल जाते थे. इसके अलावा, उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति के लिए केवल और केवल केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं. उन्होंने लिखा कि अगर पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सही काम किया होता, तो आज दिल्ली इस स्तर के प्रदूषण से ग्रस्त न होती. एलजी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते थे, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं करते थे. उन्होंने कहा, आप सबको हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते. आपके साथ भी यही हुआ. दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया.

विशेष — इसलिए दिल्ली में मोदी-शाह की हुई मुलाकात?

नीतीश काल का अंत 'निशांत' युग की शुरुआत!

पटना. बीते 22 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा न केवल प्रशासनिक बल्कि सियासी नजरिए से भी बेहद अहम रहा. चुनावी जीत के महज एक महीने बाद एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई इस बैठक ने बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

दिल्ली के सियासी गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल गई है कि बैठक का असली मुद्दा बिहार के लिए फंड या कैबिनेट विस्तार नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का भविष्य और उनके उत्तराधिकारी का चयन था.

नवंबर में मिली शानदार जीत के बाद यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अलग-अलग मुलाकात की. वैसे तो सरकारी तौर पर इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन वर्तमान राजनीति में कोई भी मुलाकात शिष्टाचार के लिए नहीं होती, वरन् सभी मुलाकातों के कुछ न कुछ मायने होते हैं. अंदरखाने की खबर यह है कि इस मुलाकात में बिहार के अगले

सियासी रोडमैप की पटकथा लिखी जा चुकी है.

मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही थी कि एनडीए गठबंधन अब अपनी 243 सीटों की जीत को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक ठोस रणनीति पर काम कर रहा है.

दिल्ली दौरे के असल मायने क्या हैं?- राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का यह दौरा सामान्य नहीं था. 22 दिसंबर 2025 को जब वे दिल्ली पहुंचे, तो माहौल में एक अलग ही गंभीरता थी. अमूमन प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री अकेले होते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ पार्टी और गठबंधन के अन्य बड़े नेताओं का होना यह बताता है कि बात सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं थी.

सन्नाटे के पीछे छिपा बड़ा संकेत

> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली को करीब से जानने वाले लोग इस बात से हैरान हैं कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी. यह उनका पुराना अंदाज नहीं है. हाल के दिनों में अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले नीतीश कुमार इस बार पत्रकारों के सवालों से बचकर निकल गए. जानकारों का कहना है कि यह खामोशी एक रणनीति का हिस्सा है. जब भी कोई बड़ा फैसला होने वाला होता है, तो अक्सर बड़े नेता इसी तरह की चुप्पी साध लेते हैं.